‘भारत के पर्यावरण की स्थिति 2026’: 99% दिन चरम मौसम

पर्यावरण-आँकड़े और विकास-मूल्यांकन | समाचार संदर्भ: 4 जून 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

4 जून 2026 को (विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व-संध्या) विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) और डाउन टू अर्थ ने ‘State of India’s Environment 2026: In Figures’ जारी किया — सरकारी आँकड़ों पर आधारित वार्षिक सांख्यिक रिपोर्ट, जिसके अनुसार 2025 में भारत ने वर्ष के 99% दिन चरम मौसम-घटनाएँ देखीं, जिनसे 4,421 लोग मारे गए और 1.741 करोड़ हेक्टेयर फसली क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ।

खबरों में क्यों

DTE/CSE की जारी-सूचना के प्रमुख निष्कर्ष: 2020-21 से 2024-25 के बीच ~97,000 हेकटेयर वन-भूमि गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित (26 राज्यों में वृद्धि); मानव-वन्यजीव संघर्ष में बढ़ोतरी — 10 राज्यों में हाथी-हमले बढ़े, 2025 की पहली छमाही में बाघों से 40 मौतें; 15 राज्य/केंद्र-शासित अधिक-दोहन (over-exploited) भूजल श्रेणी में — पंजाब, राजस्थान, हरियाणा पुनर्भरण से अधिक निकासी; प्रमुख नदी-डेल्टा अत्यधिक भूजल-निकासी से धँस रहे; ~13% भारतीय किसी बीमारी से पीड़ित (तीन दशक में दोगुना); वैश्विक वायु-प्रदूषण जनित मृत्युओं में भारत की हिस्सेदारी 2014 के 23.76% से बढ़कर 2023 में 25.34%; ambient PM2.5 जनित मृत्यु दशक में 61% बढ़ी; राज्य-प्रदर्शन में गोवा शीर्ष (नवीकरणीय ऊर्जा-हिस्सा), कचरा-प्रबंधन अधिकतर राज्यों की सबसे बड़ी चुनौती; 36 में से 32 राज्य/UT सार्वजनिक-अवसंरचना व मानव-विकास संकेतकों में आधे-से-नीचे। ‘barring one, all indicators official government data’ — पद्धति पर सह-लेखक रिचर्ड महापात्रा की टिप्पणी।

रिपोर्ट कैसे पढ़ें — आँकड़ा, संकेतक, नीति

यह सरकारी आँकड़ों का संकलन-विश्लेषण है, स्वतंत्र प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं — इसलिए इसकी ताकत तुलनीयता (समान स्रोत, समान अवधि) है और सीमा स्रोत-डेटा की गुणवत्ता। ‘99% दिन चरम मौसम’ का अर्थ कहीं-न-कहीं घटना, हर जगह नहीं। राज्य-रैंकिंग संकेतक-भार पर आधारित है — शीर्ष राज्य भी कमजोर क्षेत्र रखते हैं (गोवा: वन-आच्छादन, सीवरेज)। नीति-उपयोग: आँकड़ा चुनौती दिखाता है, कारण-विश्लेषण अलग कदम।

मुख्य तथ्य

रिलीज़: 4 जून 2026, वर्चुअल प्रस्तुति (सुनीता नारायण, DG CSE); CSE + Down To Earth; वार्षिक ‘In Figures’ सांख्यिक रिपोर्ट

चरम मौसम: 2025 में 99% दिन घटनाएँ; 4,421 मौतें; 1.741 करोड़ हे. फसली क्षेत्र क्षतिग्रस्त

वन/वन्यजीव: ~97,000 हे. वन-भूमि परिवर्तन (2020-21→2024-25, 26 राज्य); 10 राज्यों में हाथी-हमले ↑; H1-2025 में बाघ से 40 मौतें

जल/स्वास्थ्य/वायु: 15 राज्य/UT भूजल अधिक-दोहन; ~13% बीमारी-पीड़ित (30 वर्ष में दोगुना); PM2.5 मृत्यु +61% (दशक); वैश्विक हिस्सा 25.34% (2023)

राज्य-प्रदर्शन: गोवा शीर्ष; 27 राज्य कृषि/किसान-कल्याण में आधे-से-नीचे; 32/36 अवसंरचना-मानव-विकास में आधे-से-नीचे

तीन परतें — जलवायु-लागत, संसाधन-दबाव, शासन-मूल्यांकन

जलवायु-लागत: 99% दिन + 4,421 मौतें + 1.741 करोड़ हे. फसल — चरम मौसम अब 'घटना' नहीं, बुनियादी स्थिति; अनुकूलन-बजट और फसल-बीमा डिज़ाइन सीधे प्रभावित

संसाधन-दबाव: वन-परिवर्तन + भूजल-अधिक-दोहन + डेल्टा-अवक्षेप — तीनों धीमी, संचयी क्षति; वार्षिक आँकड़ा-शृंखला ही इन्हें दृश्य बनाती है

शासन-मूल्यांकन: राज्य-रैंकिंग (स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना) प्रतिस्पर्धी संघवाद का औज़ार — 'किसान-कल्याण' में 27 राज्य आधे-से-नीचा, नीति-पुनर्निर्देश का संकेत

विश्लेषण और आगे की राह

तीन परतों में देखें। (1) आँकड़ा-शासन: 'जो मापा जाता है, वही किया जाता है' (नारायण) — रिपोर्ट का मूल्य घोषणा-आँकड़ों की जगह परिणाम-आँकड़े (मौतें, हेक्टेयर, दोहन-अनुपात) केंद्र में लाना है; नीति-समीक्षा में संकेतक-आधारित ट्रैकिंग अनिवार्य। (2) संयोजी-जोखिम: चरम मौसम + भूजल-संकट + वायु-प्रदूषण अलग मंत्रालयों में बँटे, पर जोखिम संचयी — पंचायत/शहर-स्तरीय एकीकृत अनुकूलन-योजना (जल-वन-कृषि) की आवश्यकता आँकड़े रेखांकित करते हैं। (3) सीमा-सचेतता: रिपोर्ट सरकारी डेटा पर आधारित — वन-परिवर्तन/दोहन आँकड़े वही हैं जो विभाग रिपोर्ट करते हैं; वैकल्पिक माप (उपग्रह-आधारित वन-मानचित्रण विवाद) पृष्ठभूमि में रखें। ध्यान रहे: तथ्य DTE/CSE की 4 जून 2026 जारी-सामग्री से शब्दशः; पूर्ण रिपोर्ट-तालिकाओं से अतिरिक्त आँकड़े अलग सत्यापन माँगेंगे।

अवधारणा में अंतर

चरम मौसम-घटना (event — कहीं भी, किसी भी दिन) बनाम जलवायु-प्रवृत्ति (trend — दशकों की दिशा) — 99% आंकड़ा पहले का, लेकिन शृंखला दूसरे को दिखाती है। वन-भूमि 'परिवर्तन' (diversion — वैध, अनुमत) बनाम 'वन-क्षरण' (degradation) — दोनों अलग माप। और भूजल 'अधिक-दोहन' (निकासी > पुनर्भरण) बनाम भूजल 'संकट' (गुणवत्ता-सहित व्यापक)।

मेंस दृष्टि

GS-III: पर्यावरण, आपदा-प्रबंधन, जल-संसाधन; GS-II: शासन-मूल्यांकन, डेटा-आधारित नीति। उत्तर में रिपोर्ट-आँकड़े (99%, 4,421, ~97,000 हे. — attributed), संकेतक-शासन तर्क और संयोजी-जोखिम का मूल्यांकन रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'माप के बिना पर्यावरण-शासन घोषणा का शासन रह जाता है।' State of India's Environment 2026 के निष्कर्षों के आलोक में भारत की पर्यावरण-चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: रिपोर्ट + प्रमुख आँकड़े।

मुख्य भाग में: चुनौतियाँ: चरम मौसम-लागत, वन/भूजल-संकट, वायु-स्वास्थ्य; शासन-पाठ: संकेतक-ट्रैकिंग, राज्य-रैंकिंग, किसान-कल्याण चूक; सीमाएँ: स्रोत-डेटा निर्भरता; मार्ग: एकीकृत अनुकूलन, डेटा-पारदर्शिता।

निष्कर्ष में: चरम मौसम, वन, जल और वायु-स्वास्थ्य के जुड़े जोखिमों के लिए एकीकृत अनुकूलन और पारदर्शी संकेतक-निगरानी सुझाएँ; 99 प्रतिशत दिन का अर्थ देश में कहीं-न-कहीं घटना है, हर स्थान पर नहीं। स्रोत-डेटा की सीमा और आँकड़ों से कारण स्वतः सिद्ध न होने की सावधानी रखें।

स्रोत

- Down To Earth — 'SOE in Figures 2026' जारी-रिपोर्ट (4 जून 2026)
- CSE — SOE 2026 रिपोर्ट रिलीज़ (पृष्ठभूमि)

मुख्य आँकड़े DTE की 4 जून 2026 सामग्री से शब्दशः सत्यापित; रिपोर्ट स्वयं सरकारी आँकड़ों पर आधारित (CSE/DTE दावा, attributed)।

यह भी पढ़ें: हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल: मिशन घोषणा से बाजार-विश्वास की ओर।

याद रखें: SOE 2026 का संदेश सीधा है: चरम मौसम और संसाधन-संकट अब वार्षिक 'खबर' नहीं, मापी जा रही दैनंदिनी है — नीति का अगला टेस्ट इन्हीं आँकड़ों पर होगा।